महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके, इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। आज इसका प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कर्मकार कल्याण बोर्ड के दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़ें तथा इस योजना को व्यापक भ्रष्टाचार से बचाया जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Mahendra Bhatt: Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Smt. Sangeeta Yadav, (Uttar Pradesh), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

'Need to Strengthen Fiscal Equity for Balanced National Growth — Shri Tiruchi Siva; not present. Need to establish a branch of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in Nanded District of Maharashtra State - Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

Need to establish a branch of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in Nanded District of Maharashtra

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा विभाग के नांदेड़ जिले में किसानों की प्रगति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agriculture Research) की शाखा स्थापित करने की आवश्यकता है। मराठवाड़ा, जो महाराष्ट्र का एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, कई गंभीर कृषि समस्याओं का सामना कर रहा है। यहां जल की कमी, असमान वर्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दे हैं। इन समस्याओं के कारण फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है और वे विफल हो रही हैं, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में अक्सर सूखे की समस्या उत्पन्न होती है, जो स्थानिक आय स्तर पर गंभीर प्रभाव डालती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि कृषि फसलों की विविधता की कमी के चलते उनकी आय में स्थिरता नहीं रहती है। इस प्रकार सूखे की स्थिति न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, बल्कि किसानों के जीवन स्तर को भी चुनौती देती है।

माननीय उपसभापति महोदय, मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) को सूखा प्रतिरोधी फसलों, प्रभावी वर्षा जल प्रबंधन और जलवायु प्रतिरोधी कृषि तकनीकों पर अनुसंधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही विस्तार सेवाओं को प्रोत्साहित करना और स्थानीय किसानों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सरल बनाना भी आवश्यक है।

महोदय, मैं इस संदर्भ में भारत सरकार और कृषि मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि ICAR की सूखा भूमि अनुसंधान संस्थान की एक अस्थाई शाखा नांदेड़ में स्थापित की जाए, ताकि ICAR के वैज्ञानिक और अधिकारी स्थानीय कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर मराठवाड़ा के प्रत्येक गांव में नियमित रूप से किसानों से मिलकर सूखा प्रतिरोधी फसलों की जानकारी प्रदान कर सकें, जिससे इस सूखा प्रभावित क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो। ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुख्य शाखा महाराष्ट्र में नहीं होने के कारण इस संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधान के लाभ मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आर्थिक संकट के चलते मराठवाड़ा के कई किसानों ने अपने जीवन को समाप्त करने का एक अत्यंत दुखद निर्णय लिया है। मैं भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ICAR की ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक अस्थाई शाखा नांदेड़ जिले में स्थापित की जाए, जिससे किसानों को आवश्यक सहायता और जानकारी भी मिलेगी। अगर ICAR की यह ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की शाखा हमारे नांदेड़ जिले में मिलेगी, तो इस क्षेत्र में किसानों की फसलों और उनकी उत्पादकता में बहुत बड़ी प्रगति हो सकती है।

माननीय उपसभापति महोदय, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। हमारे मराठवाड़ा के किसानों की फसलों के लिए जो मिट्टी है, यह पानी नहीं पकड़ती है, इसलिए इसमें रिसर्च की आवश्यकता है और किसानों की मदद करने की बहुत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से फिर से प्रार्थना करता हूं और हमारे मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में ICAR की यह संस्था स्थापित करने की मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Dr. Sasmit Patra (Odisha). Dr. Fauzia Khan - Need for a national policy on school transport safety.

Need for a national policy on school transport safety

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, the increasing number of accidents involving school vans and buses has become a serious issue, necessitating immediate action. Despite existing State-specific laws and guidelines from the CBSE and directives from the Supreme Court, several notable enforcement challenges and fundamental issues still persist. A national study conducted by the Save Life Foundation in 2021 has found that 47 per cent school transport vehicles lack seat-belts, only 48 per cent have speed governors, 41 per cent schools have no transport manager, 25 per cent parents could verify that GPS and CCTV systems were operational in school buses,